जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 45 संख्याः 64 प्रभात बीकानेर, गुरुवार 28 सितम्बर, 2023 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रू.

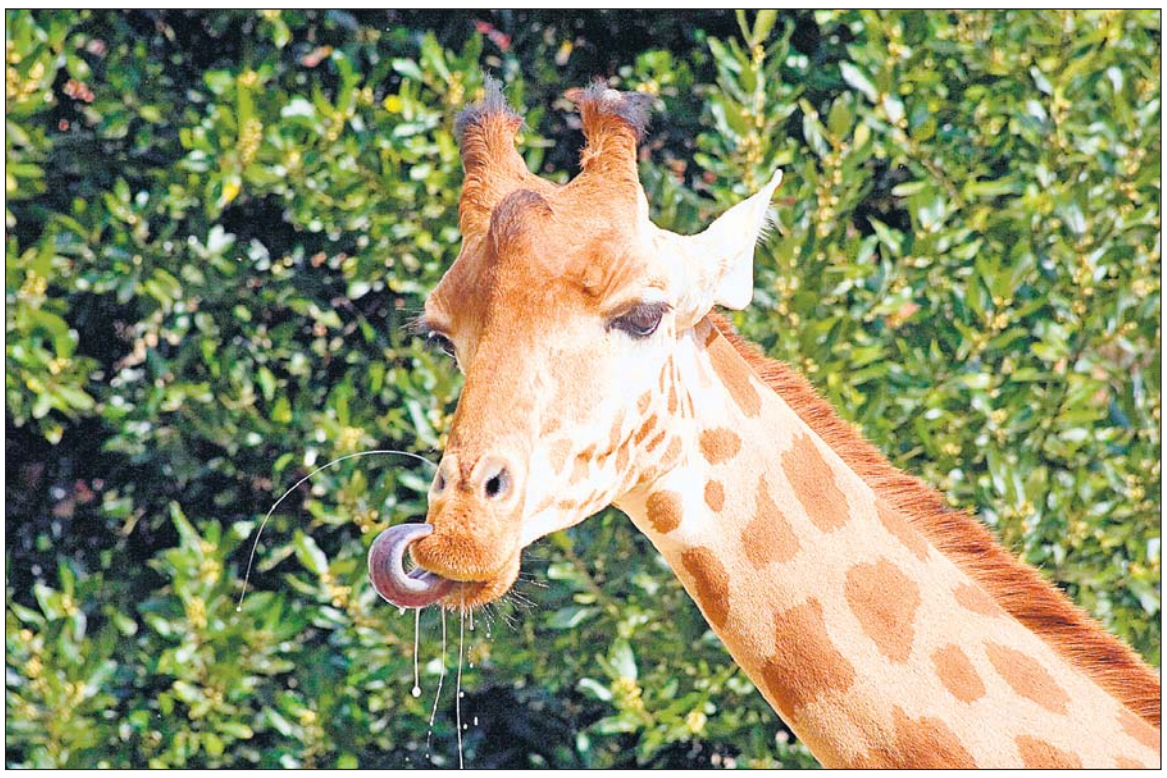

हर साल यदि सिर्फ दो कॉर्डोफैन जिराफ ही मारे जाते हैं तो भी कैमरुम के बैनोयू नैशनल पार्क में यह उपप्रजाति 15 साल में ही लुप्त हो जाएगी। युनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल ज़ूलॉजिकल सोसायटी द्वारा करवाए गए नए शोध से यह जानकारी मिली है। अफ्रीकन जर्नल ऑफ इकॉलजी में छपे इस शोध के सहलेखक सैमुअल पैनी ने कहा कि, हमें यह तो लग रहा था कि पार्क के अंदर अवैध शिकार के कारण इनकी आबादी कम हो रही है। तथापि, हमने यह उम्मीद नहीं की थी कि, विलुप्ति की नौबत इतनी जल्दी आ जाएगी। यह बेहद चिंताजनक है। कॉर्डोफैन जिराफ गंभीर रुप से संकटग्रस्त जिराफ उपप्रजाति है, जो कैमरुन, काँगो, सैंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, काँगो, व साउथ सूडान में मिलते हैं। इनकी कुल आबादी 2300 के लगभग है तथा "बनाओ नैशनल पार्क" में इनकी आबादी 300 से कम है। मांस, हड्डियों, बाल व पूंछ के लिए जिराफ का शिकार किया जाता है। इनकी खाल का गलीचों के रुप में प्रयोग होता है। हर पांच साल में एक नर व एक मादा के मरने से यह उपप्रजाति 100 साल में लुप्त हो जाएगी और हर साल एक जोड़ा लुप्त होने से 15 साल में लुप्त हो जाएगी। शोध के अनुसार, अवैध शिकार रोकना इस विलुप्ति को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। जिराफ की सबसे नाटी इस उपप्रजाति के सदस्यों का कद 3.8 से 4.7 मीटर होता है। नर की बजाय मादा के शिकार से आबादी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। मादा 4 साल में प्रजनन योग्य हो जाती है और इनका गर्भकाल 15 माह का होता है। शोध के अनुसार, पार्क में अन्य स्थानों से मादा जिराफ लाने से आबादी बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि शोध लेखक एक स्थान से दूसरे स्थान जानवरों के स्थानान्तरण के खिलाफ हैं। इसकी बजाय शोध ने सुझाव दिया है कि, जिराफ के आवास के बीच के कॉरिडोर की सुरक्षा की जानी चाहिए। कॉरिडोर होने से जिराफ स्वतः अलग-अलग क्षेत्रों में जा सकेंगे।

कांग्रेस हाई कमान ने 60 प्रतिशत विधायकों के टिकट काटने का मन बनाया

स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई ने कहा, सिर्फ जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। कांग्रेस ने राजस्थान में अपने बहुत से मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का पक्का मानस बना लिया है। राजस्थान के लिये बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने सार्वजनिक रूप से बयान दे दिया है कि मौजूदा विधायकों को टिकट दिये जाने के स्थान, आगामी विधानसभा चुनावों के टिकट वितरण के अपनाये जाने वाला इकलौता फॉर्मूला प्रत्याशी की "जीतने की क्षमता" पर आधारित होगा।

- **राहुल गांधी ने गौरव गोगोई से साफ कह दिया है कि, सुनील कानूगोलू की रिपोर्ट में जिन विधायकों की हार तय बताई गई है, उन्हें टिकट कदापि न दिया जाए।**
- **जिन विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, उनमें से अधिकांश विधायक गहलोत खेमे के हैं, जिनकी हार पक्की बताई जा रही है, पर गहलोत उन्हें हर कीमत पर टिकट दिलाना चाहते हैं।**
- **गहलोत 50 प्रतिशत टिकट मौजूदा विधायकों को दिलाना चाहते हैं। उनका कहना है कि, जिन्होंने उनकी सरकार बचाई उन विधायकों को टिकट मिलना ही चाहिए।**
- **गहलोत का कहना है कि, जिन विधायकों ने सरकार गिराने की कोशिश की उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए।**

सूत्रों के अनुसार, राजनैतिक रणनीतिकार तथा विश्लेषक सुनील कानूगोलू तथा उनकी टीम ने अपना यह सर्वे कांग्रेस नेतृत्व को भेज दिया है कि सभी विधायकों तथा खासतौर से सभी मंत्रियों के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी भावना है। उन्होंने सिफारिश की है कि अगर पार्टी को चुनाव में टक्कर देनी है तो मौजूदा विधायकों के कम से कम 50 प्रतिशत टिकट काटना जरूरी होगा।

सूत्रों का भी कहना है कि कांग्रेस ने टिकट वितरण उस समय तक रोके रखा है, जब तक चुनावों की घोषणा नहीं हो जाती। ऐसा करने का कारण यह बताया गया है कि विधानसभा चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं, आगे भी खिसक सकते हैं तथा "एक राष्ट्र एक चुनाव" का विचार क्रियान्वित किया जा सकता है। हालांकि वेणुगोपाल ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर दी थी कि राजस्थान के लिये कांग्रेस के टिकटों की घोषणा सितम्बर के शुरु में हो जायेगी।

सूत्रों ने कहा कि टिकट-वितरण में विलम्ब का मुख्य कारण कांग्रेस का यह दृढ़ निश्चय है कि उन विधायकों के टिकट काटे जायेंगे, जो बुरी तरह हारते नज़र आ रहे हैं।

यह भी समझा जाता है कि अशोक गहलोत पूरी जोरदारी के साथ कह रहे हैं कि राजेन्द्र गुढ़ा के निष्कासन के बाद, राज्यसभा चुनावों में 121 विधायकों ने कांग्रेस का समर्थन किया था। गहलोतन ने यह भी कहा है कि इन विधायकों को उस समय भी सरकार को सहयोग दिया था, जब कुछ विधायकों तथ्शा अन्य लोगों ने इस सरकार को गिराने की कोशिश की थी। इस प्रकार, गहलोत का तर्क यह है कि टिकट उन विधायकों के काटे जाने चाहिये, जिन्होंने उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाराष्ट्र में भाजपा लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना चाहती है

अक्टूबर 2024 में राज्य के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव अगले साल अप्रैल-मई में निर्धारित हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। भारतीय जनता पार्टी का केन्द्रीय नेतृत्व अपनी महाराष्ट्र इकाई के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि राज्य के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही करवा लिए जाएं। उनका मानना है कि दो टिकटों वाला चुनाव और प्रधानमंत्री की जोरदार अपील पार्टी के पक्ष में काम करेगी।

- **पार्टी को उम्मीद है कि, दोनों चुनाव एक साथ होने से मोदी फैक्टर ज्यादा प्रभावी ढंग से कारगर होगा।**
- **महाराष्ट्र में भाजपा के नेताओं का कहना है कि, दोनों चुनाव एक साथ हुए तो विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी होंगे।**
- **पार्टी चाहती है कि, राज्य में अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया जाए, इसलिए अधिकांश सीटों पर भाजपा अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है।**

राज्य विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2024 में हैं लेकिन राज्य भाजपा उन्हें अगले वर्ष अप्रैल-मई में लोकसभा के साथ ही करवाना चाहती है।

नेतृत्व की आंख महाविकास अगाड़ी में शामिल विपक्षी पार्टियों और शिव सेना के एक गुट के साथ अपने गठबंधन के कार्यकलाप पर लगी हुई है।

राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने 2023-24 का बजट सबको खुश करने वाला रखा है। पार्टी के थिंक टैंक का मानना है कि हाल में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हुआ गठबंधन लोगों को "फील गुड" करवाने में मदद कर सकता है।

विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ करवाने, जहां मोदी की अपील और राष्ट्रीय मुद्दे भी मतदाता के दिमाग में रहेंगे और ये मतदाताओं को प्रभावित करेंगे। ये कहना है मंत्रिमण्डल के एक सदस्य का जो राज्य की चुनावी रणनीति से वाकिफ हैं।

मंत्री ने कहा, "राज्य में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने सुझाव दिया है और केन्द्रीय नेतृत्व अब इस विकल्प पर विचार कर रहा है। वह उचित समय पर कदम उठाएगा। राज्य के चुनाव लोकसभा चुनाव के 5-6 माह बाद ही है इसलिए यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए।

भाजपा राज्यों व केन्द्र के चुनाव एक साथ होने का फायदा उठाकर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना एवं नैशनलिस्ट, कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) के कमज़ोर और अवसरवादी गठबंधन की दरारों को उघाड़ना और बढ़ाना चाहती है। मंत्री का कहना है कि, महाराष्ट्र विकास अगाड़ी (एम.वी.ए.) तिकड़ी चुनावों की घोषणा तक एक साथ बने रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कह सकते। चुनाव अभियान के दौरान ही वो टूट सकते हैं,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है।?
ऑटोमेटिक
कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
कॉकलियर इम्पलांट, ऑटिजम
डिले स्पीच, हकलाना, तुतलाना
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
सम्पर्क- 94602 07080

अमित शाह और नड्डा का शानदार स्वागत

जयपुर 27 सितंबर । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जयपुर पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पर उनका स्वागत किया।

स्वागत करने वाले नेताओं में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश चुनाव प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी नितिन पटेल, कुलदीप बिश्नोई, केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, प्रदेश सह प्रभारी विजया रहाटकर, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष अजयपाल सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति

- **एयरपोर्ट पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित तमाम बड़े नेता शाह व नड्डा के स्वागत के लिए मौजूद थे।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान में भाजपा केन्द्रीय मंत्रियों व कद्दावर सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारेगी

गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, राज्यवर्धन राठौड़ और दिया कुमारी का नाम चर्चा में है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। संकेत हैं कि, राजस्थान विधानसभा चुनावों में, बड़ी संख्या में केन्द्रीय मंत्रियों और वर्तमान सांसदों को चुनाव मैदान में उतार कर भाजपा मध्य प्रदेश की अपनी रणनीति को दोहरायेगी। भाजपा ने जहाँ, मध्य प्रदेश के लिए प्रत्याशियों की दो सूचियाँ जारी कर दी हैं, वहीं पार्टी ने राजस्थान सहित उन अन्य राज्यों की लिस्ट जारी नहीं की है जहाँ निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं। इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि, भाजपा हाई कमान वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के चेहरे के रुप में घोषित नहीं करना चाहता है।

- **इस प्रकार भाजपा हाई कमान ने संकेत दे दिया है कि, वह वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाने के पक्ष में नहीं है। भाजपा के 30 प्रतिशत मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की तैयारी भी कर ली है।**
- **भाजपा ने राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की रणनीति पर ही अमल किया है।**

राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए जिन केन्द्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, उनमें, जल शक्ति मंत्री, गजेन्द्र सिंह शेखावत एवं विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नाम प्रमुख हैं। भाजपा थिंक टैंक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एवं दिव्या सिंह, (क्रमशः जयपुर ग्रामीण व राजसमंद से सांसद) को विधानसभा चुनाव लड़वाने के विकल्प पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार यह भी संभावना है कि, भाजपा 30 प्रतिशत वर्तमान विधायकों के टिकट काट सकती है।

मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए, भाजपा ने तीन केन्द्रीय मंत्रियों, नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा है। इनके अलावा चार सांसदों, राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और उदयप्रताप सिंह को भी टिकट दिया गया है, जिससे ये चर्चाएं शुरु हो गई हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया जा रहा है।

भाजपा के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिनका नाम भी प्रत्याशियों की सूची में है, अपने चयन से खुश नहीं हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिधूड़ी टोंक में भाजपा के प्रभारी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। भारतीय जनता पार्टी सांसद रमेश बिधूड़ी, जिन्होंने अभी हाल ही, संसद में बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ अभद्र एवं मुस्लिम विरोधी टिप्पणियाँ की थीं, को राजस्थान में टोंक चुनाव क्षेत्र का पार्टी प्रभारी नियुक्त किया गया है।

- **लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ धर्म आधारित अपमानजनक टिप्पणी करने वाले सांसद रमेश बिधूड़ी की इस नियुक्ति को राजनैतिक हल्कों में "पुरस्कार" बताया जा रहा है, जबकि भाजपा नेतृत्व उन्हें लोकसभा में गलत टिप्पणी के लिए नोटिस दे चुका है।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा राजस्थान में "वसुंधरा फैक्टर" को शून्य करने की तैयारी में

मध्य प्रदेश की तर्ज पर केन्द्रीय मंत्रियों व सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। पांच राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए चल रहे भीषण युद्ध में भाजपा वहां के कद्दावर नेताओं को खड़ा करना चाहती है ताकि वह मई में हुई कर्नाटक की हार तथा हाल के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन से मिली 3-4 की हार से उबर सके।

भाजपा के एक शीर्ष नेता ने बताया कि पार्टी इस वर्ष होने वाले पांच राज्यों के चुनाव में "सामूहिक नेतृत्व", "कद्दावर नेताओं और मोदी फैक्टर पर निर्भर रहना चाहती है।"

सूत्रों ने यह भी कहा कि पार्टी किसी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी, विशेषकर हिंदी भाषी मध्य प्रदेश और राजस्थान में। यह प्रयास है क्षेत्रीय नेताओं की महत्त्वाकांक्षाओं और प्रतिद्वंदिता को नियंत्रण में रखना और "व्यक्ति से बढ़कर पार्टी" का नारा बुलंद करना।

सीधे शब्दों में, भाजपा को उम्मीद है कि बड़े नाम उसे कमज़ोर जगहों पर सीटें जितवा देंगे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील भी पार्टी को चुनाव का एक दौर और जितवाएगी और मुख्यमंत्री के पद पर नाम खुला रखना क्षेत्रीय नेताओं को ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

सूत्रों ने कहा कि प्रयास यह है कि भाई-भतीजावाद को खत्म किया जाए, वंशवादी राजनीति से दूर रहा जाय,

- **सूत्रों का कहना है कि, वसुंधरा राजे भले ही राजस्थान में भाजपा की सबसे ताकतवर एवं प्रभावशाली नेता मानी जाती हैं, पर इस बार उनकी वापसी की संभावना बहुत कम है।**
- **भाजपा हाई कमान दो बार मुख्यमंत्री रह चुकीं वसुंधरा राजे को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा और यह संभावना भी नहीं है कि, वसुंधरा एक विधायक के रूप में किसी अन्य मुख्यमंत्री के अधीन विधानसभा में बैठेंगी।**
- **भाजपा की योजना है कि, जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है, वहां मोदी फैक्टर पर ही चुनाव लड़ा जाएगा।**
- **समझा जाता है कि, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा इसी योजना पर अमल करेगी।**

विशेषकर इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं।

इस योजना की कुछ झलक इस सप्ताह मध्य प्रदेश में देखने को मिलीं।

इसी तर्ज पर भाजपा की राजस्थान में पहली सूची, जो शायद 49 सीटों की है, शीघ्र आने वाली है, यह लिस्ट जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की मुलाकात के बाद जारी हो सकती है।

राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरे हैं केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और अर्जुनराम मेघवाल, राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, लोकसभा सांसद दिव्या कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़ और सुखबीर सिंह जौनपुरिया।

70 वर्षीय वसुंधरा राजे दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और सिंधिया राज परिवार की सदस्य हैं, लेकिन उनका इस बार उनका लौटना मुश्किल है, हालांकि उन्हें राज्य में भाजपा का सबसे कद्दावर और प्रभावशाली नेता माना जाता है।

गैर-भाजपा मतदाताओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली राजे से पार्टी किस तरह पेश आती है यह महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वे किसी अन्य मुख्यमंत्री के मातहत विधायक होकर तो विधानसभा में नहीं बैठ सकतीं।

मध्य प्रदेश में तीन केन्द्रीय मंत्री, चार सांसद और राष्ट्रीय माहसचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रत्याशी हैं जबकि अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चन्द्रबाबू की अपील पर 3 अक्टूबर को सुनवाई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। सर्वोच्च न्यायालय की एक नई बैंच आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू की उस याचिका की सुनवाई 3 अक्टूबर को करेगी, जिसमें उन्होंने राज्य के स्किल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन में कथित 371 करोड़ रू. के घोटाले में उनके खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. को रद्द करने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी इस याचिका की सुनवाई से बुधवार को स्वयं को अलग कर लिया।

- **आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू को 9 सितम्बर को 371 करोड़ रू. के कौशल विकास घोटाले में गिरफ्तार किया गया था।**

जब न्यायमूर्ति भट्टी, जो न्यायमूर्ति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)